10 मिलियन किसानों को प्राकृतिक खेती की प्रथाओं में लाना और जलवायु सहनशील फसलों पर ध्यान केंद्रित

बजट में किसान, युवा, व्यापारियों का रखा गया विशेष ध्यान

मोदी 3.0 सरकार का बजट उनकी पिछली सरकार के भारत को बदलने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखा है; जिसमें राजकोषीय घाटा 4.9 प्रतिशत तक कम हो गया है और 4.5 प्रतिशत स्पष्ट दृष्टिकोण में है। बजट ने कृषि क्षेत्र को बहुत जरूरी प्रोत्साहन दिया है। कृषि पर 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जिसका उद्देश्य 10 मिलियन किसानों को प्राकृतिक खेती की प्रथाओं में लाना और जलवायु सहनशील फसलों पर ध्यान केंद्रित करना है। बजट का एक प्रमुख आकर्षण विनिर्माण क्षेत्र को दिया गया, जो हमारे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। एमएसएमई हमेशा से ही ऋण की कमी से जूझते रहे हैं और बजट ने इन चिंताओं को सीधे तौर पर संबोधित किया है।

प्रो. राम कुमार कांकानी, निदेशक, आइआइएम रायपुर। ● नईदुनिया आर्काइव

बजट में एक क्रेडिट गारंटी योजना पेश की गई है जो एमएसएमई को बिना संपार्श्विक या तृतीय-पक्ष गारंटी के मशीनरी खरीदने के लिए टर्म लोन प्राप्त करने की अनुमति देगी। यह एमएसएमई के लिए एक बड़ा कदम है। कस्टम ड्यूटी में कटौती, विशेष रूप से मोबाइल पार्ट्स की (15 प्रतिशत तक घटाई गई) व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और भविष्य में भारत को एक प्रमुख वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला खिलाड़ी के रूप में विकसित करने में मदद करेगी। इसके अलावा, ई-कामर्स निर्यात केंद्रों की स्थापना छोटे फर्मों और कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों का आसानी से अन्वेषण करने में मदद करेगी। इससे उन्हें अपना बाजार आधार बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में उनके कुल योगदान को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यह एक शानदार कदम है, क्योंकि भारत का कुल ई-कामर्स निर्यात प्रवेश कम है, और यह भारत की पूरी क्षमता का लाभ उठाने में मदद कर सकता है।

सरकार ने एफडीआइ में गिरावट को भी पहचाना है और इसके परिणामस्वरूप एफडीआइ मानदंडों को आसान बनाने के लिए सुधारों का वादा किया है, जिससे उम्मीद है कि एफडीआइ पहले के स्तर तक पहुंचेगा और यहां तक कि इसमें वृद्धि भी होगी। अंत में, सरकार का रोजगार सृजन के लिए 2 करोड़ रुपये का आवंटन समय पर है क्योंकि भारतीय कार्यबल का आकार बढ़ रहा है। इस संदर्भ में, 20 लाख युवाओं के कौशल के लिए सीएसएस कार्यबल को अधिक रोजगार योग्य बनाएगा और विनिर्माण क्षेत्र को भी बढ़ने में मदद करेगा। अब, एक चीज जो वेतनभोगी वर्ग की मदद करेगी, वह है मानक कटौती में वृद्धि, साथ ही कर स्लैब का पुनर्गठन। कुल मिलाकर बजट अच्छी तरह से संतुलित है, और सभी के लिए कुछ न कुछ प्रदान किया गया।

Nayidunia,24th July,2024,P.01